DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day

Tuesday **20260818**

.

सुनवाई

डीएमसी भेजी गई शिकायत, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई से पहले मेडिकल ओपिनियन का इंतजार

थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होने पर स्टेटस रिपोर्ट तलब

गौरव बाजपेई

नई दिल्ली। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने आईवीएफ उपचार और पीजीटी-एम जेनेटिक टेस्टिंग के बावजूद थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चे के जन्म के मामले में पुलिस को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। हाइब्रिड माध्यम से हुई सुनवाई में लिंक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकुरन ने आदेश पारित किया।

शिकायतकर्ता के वकील राहुल कुमार के अनुसार, पुलिस ने शिकायत और संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) को भेज दिए हैं। फैसले के मुताबिक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से पहले मेडिकल ओपिनियन लिया जाना है। डीएमसी की जांच और मेडिकल ओपिनियन अभी लंबित है। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

मामला फरीदाबाद निवासी दंपती का है। उन्होंने 25 अप्रैल 2022 को लाजपत नगर स्थित वर्ल्ड इन्फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में डॉ. विद्या सिन्हा से इलाज शुरू कराया था। दंपती ने डॉक्टर को अपना मेडिकल इतिहास, दो बच्चों की मौत और थैलेसीमिया मेजर जैसे आनुवंशिक रोग को लेकर चिंता बताई थी। आरोप है कि डॉक्टर ने सही आईवीएफ और जेनेटिक टेस्टिंग से स्वस्थ बच्चे का आश्वासन दिया था।

मेडजीनोम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 18 जुलाई 2022 और 21 अगस्त 2023 को भ्रूण बायोप्सी सैंपल लिए। 20 सितंबर 2023 की रिपोर्ट में एम्ब्रियो को पीजीटी-एम और पीजीटी-ए के आधार पर ट्रांसफर के लिए टॉप चॉइस बताया गया था।

सर गंगाराम अस्पताल में हुई थैलेसीमिया की पुष्टि

23 जून 2025 को बच्चे को सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में थैलेसीमिया मेजर की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने आजीवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन चेलेशन थेरेपी और लगातार चिकित्सा प्रबंधन की सलाह दी। दंपती का दावा है कि उन्होंने इलाज पर करीब 16 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन सेंटर और डॉक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 2 जून 2026 को अमर कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी दिन डीसीपी (दक्षिण) और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी शिकायत भेजी गई।

अब राजीव गांधी अस्पताल में लगेगी जीटीबी की इमरजेंसी

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं को 18 अगस्त से अस्थायी रूप से राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ताहिरपुर में स्थानांतरित किया जाएगा।

अस्पताल प्रशासन ने 14 अगस्त को सार्वजनिक सूचना जारी कर मरीजों, एंबुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इसकी जानकारी दी है। मरम्मत और रिनोवेशन के कारण इमरजेंसी सेवाओं को स्थानांतरित करने की तैयारी पहले से चल रही थी।

ब्लॉक नंबर-4 में मिलेगी इमरजेंसी सुविधा : अस्पताल प्रशासन के अनुसार 18 अगस्त की सुबह नौ बजे से जीटीबी की एएंडई

18 से बदलेगा इमरजेंसी का पता, स्त्री-प्रसूति और बाल रोग की सेवाएं जीटीबी में ही

सेवाएं, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के ब्लॉक नंबर-4 में संचालित होंगी।

मरीजों को अस्पताल के गेट नंबर-4 से प्रवेश मिलेगा। प्रशासन ने एंबुलेंस सेवाओं और आम लोगों से नए स्थान की जानकारी रखने की अपील की है।

स्त्री एवं प्रसूति, बाल रोग की इमरजेंसी जीटीबी में ही : जीटीबी अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग (गायनी) तथा बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) की आपातकालीन सेवाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है।

फाइल

ये सेवाएं पहले की तरह जीटीबी अस्पताल के एमसीएच ब्लॉक से ही संचालित होती रहेंगी।

मरम्मत के बाद इमरजेंसी को किया जाएगा अपग्रेड : जीटीबी अस्पताल के पुराने इमरजेंसी ब्लॉक में मरम्मत और रिनोवेशन के लिए इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी अस्पताल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई थी।

बचपन सुरक्षा के नाम पर सख्त कानून बनाने वाले अमेरिका में बदल रही धारणा, 13 राज्यों ने नियमों में दी ढील

बच्चों को अकेले पार्क में या आसपास जाने देना गलत नहीं...यह आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका

इयान फ्रिश, द न्यूयॉर्क टाइम्स

अटलांटा। क्या बच्चों को अकेले खेलने के लिए घर से बाहर भेजना, पार्क जाने देना या आसपास की दुकान से सामान मंगाना अपराध हो सकता है? इस पर अधिकांश लोग यही कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ अमेरिकी राज्यों में सख्त कानूनों के कारण ऐसी स्थिति में अभिभावकों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है।

अटलांटा में कुछ समय पहले ऐसा एक मामला सामने आया, जब छह साल के बच्चे को अकेले पार्क में खेलते देखकर एक महिला ने बाल कल्याण विभाग में उसके अभिभावकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद मैलरी शर्ली और उनके पति क्रिस्टोफर प्लेसेंट्स से पूछताछ हुई। हालांकि, लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपील के बाद अब इस दंपती को आरोपों से बरी कर दिया गया है। वैसे, फ्री-रेंज किड्स आंदोलन के प्रति बढ़ते जनसमर्थन का असर भी दिख रहा है। 13 राज्य अपने बाल-उपेक्षा कानूनों में ढील दे चुके हैं ताकि बच्चों को अकेले बाहर खेलने की कानूनी आजादी मिल सके।

पिछली पीढ़ी की तुलना में बढ़ीं पाबंदियां

द ब्रिटिश चिल्ड्रन प्ले सर्वे के मुताबिक, पिछली पीढ़ी को औसतन 8.9 वर्ष की उम्र में अकेले बाहर खेलने जाने की आजादी मिल जाती थी लेकिन आज के बच्चों को अकेले बाहर जाने की अनुमति औसतन 10.7 वर्ष की उम्र में मिलती है। यानी स्वतंत्रता मिलने की उम्र लगभग 2 साल आगे बढ़ गई है।

34% बच्चे स्कूल के बाद बाहर खेलने नहीं जाते

60 मिनट रोज खेलना-कूदना चाहिए 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को

20% के करीब सप्ताहांत में भी बाहर नहीं खेलते

सुरक्षा पर हर देश में अलग-अलग राय

- **फिनलैंड, जर्मनी व नॉर्वे :** बच्चों को सबसे अधिक स्वतंत्रता, 7-8 की उम्र से अकेले स्कूल, खेलने जाने की छूट।
- **ब्रिटेन, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया :** इन देशों में सुरक्षा चिंताओं के कारण बच्चों की स्वतंत्रता का स्तर मध्यम से कम है।
- **दक्षिण एशियाई व एशियाई देश :** शहरों में यातायात और भीड़भाड़ के कारण वयस्कों की निगरानी में खेलने की आजादी।

weeks to respond to them. agency's submissions. tion and regular monitoring.

On cam: Guard fills syringes for patients at Noida hospital

Ayantika.Pal@timesofindia.com

Noida: A security guard with no clinical training was filmed filling syringes with injectable medicine at district hospital in Sector 39 and handing them to a staff nurse to administer to patients in the emergency ward.

The video, recorded on Aug 14, has triggered an inquiry into how a non-medical employee was allowed to perform a task that requires training and strict medication-safety protocols.

The footage shows the guard, deployed on the hospital's fifth floor, opening medicine ampoules and drawing their contents into syringes at a counter while the nurse stands nearby. Officials said around 15-20 ampoules of ranitidine were prepared this way and administered to patients. Ranitidine is a medicine used to reduce the production of stomach acid and is prescribed for conditions such as acid reflux and peptic ulcers.

According to hospital officials, the nurse had been attending to patients during an emergency and had asked the guard to assist her. The hospital management, however, clarified that the circumstances — however pressing — did not justify the arrangement.

Officials said around 20 ampoules of ranitidine were prepared this way and administered to patients

"The nurse was busy attending to some patients in an emergency. So, she asked the guard to help her. However, no matter what the reason was, such action is not acceptable," said Ashok Kumar Jha, the chief medical superintendent.

Jha said the hospital took immediate action after the video came to light and removed staff nurse Richa Kumari and guard Sunil Kumar from duty. Both were outsourced employees. Kumar was deployed through an Aligarh-based private agency, which was also served a notice seeking an explanation.

A senior doctor at the hospital said preparing an injection involves more than simply transferring medicine into a syringe. The person must identify the correct drug and dose, open the ampoule safely, prevent contamination and ensure there is no air in the syringe.

"Drawing medication from an ampoule into a syringe and preparing it for injection is a clinical procedure that requires training, experience and strict attention to detail," the doctor said.

An error in any of these steps can expose patients to wrong doses, contamination or other potentially serious complications. "A security guard, who is not trained or authorised to perform clinical procedures, should not be involved in preparing syringes or handling injectable medicines under any circumstances," the doctor clarified.

The incident also prompted the hospital to review the role of outsourced workers. "Guards are deployed for security-related duties and are not authorised to undertake clinical responsibilities involving medication preparation or patient treatment," an official said.

"Further action would be taken based on the findings of the inquiry and the response received from the outsourcing agency," Jha added.

You've got mail: Drugs now being circulated in Goa through courier

Pavneet Singh Chadha
Panaji, August 17

Police officers meet representatives of postal service providers for assistance

Anti-narco action

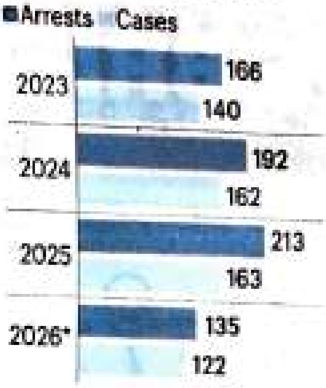

*DATA UNTIL AUGUST 12, 2026; SOURCE: GOA POLICE

Goa Police has now created a WhatsApp group for coordination with courier service operators. FILE

DEAD-DROP DELIVERY: After sending money to the seller, the buyer gets coordinates for the location where a courier delivery partner would hand over the parcel. The rider believes the contents are legitimate.

EARLIER THIS year, Goa Police intercepted a consignment of hashish being smuggled into the state.

More than the act of smuggling, though, it was the mode through which the contraband was being transported into the state that left the police worried. The hashish packets were found concealed in the bottom of a steam iron, which was posted in a package being delivered at the hands of an unsuspecting driver.

Concerned at the possibility of many more such cases, the Goa Police have decided to take the assistance of courier and postal service operators besides delivery partners to curb drug trafficking in the coastal state.

The initiative is part of a broader three-year roadmap as part of 'Nasha Mukt Bharat Abhiyan'.

Senior police officers recently held an awareness meeting with at least 75 representatives from courier and postal service providers across Goa.

During the meeting, the anti-narcotics cell informed the operators about an emerging technique among traffickers to conceal consignments, especially to smuggle cannabis and hashish, in small courier parcels and through the postal services network.

'Dead-drop method'

The police noticed that increasingly traffickers have been using a "dead-drops" delivery method to smuggle narcotics. After the buyer transfers money to the seller, they are sent coordinates of a particular location to retrieve the drugs from a rider. The drugs are often ferried by unsuspecting courier delivery partners, who are under the impression that they are handing over a legitimate parcel.

The aim of the awareness meeting was to sensitise the courier and postal service operators about common concealment methods used by traffickers and to look for "suspicious consignments", especially the ones with pseudonymous bookings, incomplete sender or receiver details, unusual packaging, and high-value parcels with inconsistent declarations.

"Courier and postal service providers are key stakeholders to prevent the misuse of their services by drug traffickers. We flagged the importance of proactive vigilance, strict adherence to KYC norms, verification of consignor and consignee details of parcels, and timely reporting of suspicious consignments to law enforcement agencies," said a senior police official, requesting anonymity.

Advantage anonymity

"This 'drop-dead' method has become quite popular due to the relative anonymity it allows the traffickers. The courier service operators, in a way, end up unknowingly facilitating the transportation of narcotics," the police officer added.

According to an analysis by anti-narcotics cell, which was shared at a zonal coordination meeting earlier this month, the most commonly seized drugs in Goa include ganja, charas, LSD, MDMA/ecstasy and cocaine.

Though cocaine is smuggled internationally and makes its way to Goa through other states like Delhi and Karnataka, cannabis (ganja) is trafficked here from Jharkhand and Odisha, according to police analysis. Charas is trafficked to Goa from Himachal Pradesh and Nepal while LSD largely makes its way into Goa from Kerala. Methamphetamine is sourced from Kerala and Bengaluru and ecstasy/MDMA is trafficked to Goa from Kerala, Maharashtra and Delhi.

A similar assessment in 2023 found that cocaine is sourced from South American countries and makes its way to Goa via the sea route, primarily through shipping containers. LSD paper is brought in flights, concealed in books in luggage while hashish (charas) is trafficked to Goa from Himachal and other north Indian states besides Nepal through rail route and via bus.

According to the police presentation, offenders use discreet methods for procurement, storage and distribution of drugs. "Social media platforms, courier services, rented premises, tourist gatherings, and nightlife events are sometimes misused for drug circulation. Coastal belts, tourist areas, nightlife zones, and party locations remain vulnerable to drug-related activities," the report stated.

Rise in cases

In 2023, Goa police arrested 166 people, including 21 foreign nationals, and registered 140 cases for smuggling narcotics. The number of arrests increased to 192 in 2024 and 213 in 2025. Cases lodged also went up to 162 and 163 in 2024 and 2025, respectively. Until August 12, 2026, 135 people have been arrested and at least 122 cases registered.

Police said the road map to end drug-trafficking involves four pillars: Enforcement, intelligence and operations; precursors and synthetic drugs control; demand and harm reduction; and capacity building and coordination. "We have created a WhatsApp group for coordination with courier service operators and some delivery partners. If they spot any suspicious parcel, especially near schools and clubs in the coastal belt, we have asked them to report to police. The idea is also to identify new patterns and get to the source. A challenge we face is there is no regulatory framework overseeing private courier services," the police officer said.

fused to give up on promotion finally gets his due

POSTAL REG. NO. DL (ND)-11/6057/2015-16-17 "Licensed to post without prepayment"

दवाओं के ओवरडोज से बचाएगा नया डिवाइस

वर्जीनिया के शोधकर्ताओं ने बनाया हाथ में लगानेवाला पैच

तकनीक

वर्जीनिया, एजेंसी। दवाओं के ओवरडोज के मामलों में अक्सर मरीज की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि समय पर उसे दवा देने के लिए आसपास कोई मौजूद नहीं होता।

अब अमरीका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो अकेले होने पर भी मरीज की जान बचा सकती है। वैज्ञानिकों ने एक सिक्के के बराबर आकार का स्मार्ट पहननेवाली पैच तैयार की है, जो शरीर में फेंटानिल का पता चलते ही खुद-ब-खुद नालोक्सोन दवा रिलीज कर देता है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका 'एडवांस्ड साइंस' में प्रकाशित हुई है।

12 लोग हर हफ्ते भारत में ओवरडोज से मौत के शिकार होते हैं

दो करोड़ से अधिक लोग ओपिओइड्स का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं

भारत में भी उपयोग

भारत में भी कैंसर या अत्यधिक दर्द से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए फेंटानिल का सीमित चिकित्सकीय इस्तेमाल होता है। यदि यह स्मार्ट पैच तकनीक क्लिनिकल ट्रायल पास करके बाजार में आती है, तो अनजाने में होने वाले ओवरडोज से मरीजों को सुरक्षा मिलेगी।

ओवरडोज बड़ी समस्या

अक्सर डॉक्टर मरीजों को दर्द से राहत के लिए ओपिओइड दवाएं लिखते हैं, लेकिन गलती से या भूलवश ज्यादा खुराक लेने से ओवरडोज हो जाता है। प्रोफेसर वुजिन सन के अनुसार, यह पैच दर्द की दवा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में होने वाले ओवरडोज से जान बचाने वाले टूल के रूप में काम करेगा।

| लाचारगी | पिता का आरोप- सांसद की सिफारिश कराने से नाराज डॉक्टर अब ऑपरेशन करने में कर रहे आनाकानी, कहीं और जाकर इलाज कराने के लिए भी कहा जा रहा

बेटी की सर्जरी के लिए 14 साल से एम्स के चक्कर लगा रहा पिता

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। सर्जरी की लंबी तारीख मिलने की बात तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अक्सर सामने आती है, लेकिन कोटा के रहने वाले मुकेश कुमार 14 साल से अपनी बेटी के दिल का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली एम्स के चक्कर काट रहे हैं।

वर्ष 2012 में अपनी पौने दो साल की बेटी के दिल के छेद का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे मुकेश को डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए सितंबर 2015 की तारीख दी थी, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं किया गया। बच्ची अब 16 साल की हो चुकी है और अपनी बीमारी के साथ ही जीवन जी रही है। कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले कुमारपुर कोटा निवासी मुकेश कुमार का कहना है कि उनकी बेटी तन्वी के जन्म से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट (दिल में छेद) है। पहली बार वे 10 अक्तूबर 2012 को दिल्ली एम्स में उसे दिखाने आए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा और 2 सितंबर 2015 को बुलाया। बाद में इस तय तारीख को बदलकर 16 नवंबर 2015 कर दिया गया। इसके बावजूद दिसंबर में बुलाया गया और तन्वी को भर्ती कर लिया गया। आरोप है कि ठंडी में बीमारी की बात कहकर सर्जरी टाल दी। फिर 4 जनवरी, 2016 को बुलाया गया। इसके बाद बार-बार तारीख बदलने पर सर्जरी नहीं हुई।

2012 में पौने दो साल की बच्ची के दिल की सर्जरी करने के लिए सितंबर 2015 की तारीख दी थी

■ हैदराबाद में इस सर्जरी का खर्च छह लाख रुपये है और बच्ची के पिता इतनी रकम जुटाने में असमर्थ

1.55 लाख रुपये और चार यूनिट रक्त भी ले लिया

मुकेश ने आरोप लगाया कि 4 अप्रैल 2014 को एम्स के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए उनसे 1.25 लाख रुपये जमा कराए और चार यूनिट रक्त भी लिया। सर्जरी के लिए 2 सितंबर 2015 की तारीख दी गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। उनका आरोप है कि इसके बाद भी मामला लगातार टाला जाता रहा। डॉक्टर ने दवा कंपनी के प्रतिनिधि जगदीश का नाम लिया। उसने 30 हजार रुपये लिए और उसे अस्पताल पहुंचाने की बात कही।

कहीं सांसद के पीए का फोन तो वजह नहीं

तन्वी के पिता मुकेश का आरोप है कि ऑपरेशन की तारीख बार-बार बदलने से परेशान होकर उन्होंने क्षेत्रीय सांसद से मदद मांगी। सांसद के पीए ने एम्स के संबंधित डॉक्टर को फोन किया, जिस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। मुकेश का आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर नाराज हो गए और ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। वे उन्हें कभी जोधी पर तो कभी हैदराबाद के अस्पताल में इलाज की सलाह दे रहे हैं। मुकेश के मुताबिक, हैदराबाद में सर्जरी का खर्च छह लाख है।

> यह चिंता का विषय है। मामले की जांच की जाएगी और इस समस्या का समाधान कराया जाएगा।
> -डॉ. रीमा दादा, मीडिया प्रभारी, एम्स दिल्ली

अपने दफ्तरों की ओर जाने में देरी हुई। दोपहर बाद हालात और बिगड़ गए।

सर्जरी से वजन घटाकर किशोर को नया जीवन

नई दिल्ली, प्रसं। भारी वजन के चलते सांस लेने में गंभीर परेशानी, सोने में दिक्कत और त्वचा संक्रमण से जूझ रहे 275 किलोग्राम वजनी किशोर के पेट की सर्जरी करके 52 किलो वजन घटाकर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे नया जीवन दिया।

अत्यधिक मोटापे की वजह से किशोर सामान्य कार में बैठने में भी सक्षम नहीं था और उसे अस्पताल तक मैटाडोर में लाया गया। सर गंगाराम अस्पताल के लीड बैरिएट्रिक सर्जन डॉ. दक्ष सेठी ने बताया कि 16 वर्षीय किशोर गंभीर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (सोते हुए बार-बार सांस रुकना और चालू होने) की भी समस्या है। उसे करीब दो सप्ताह तक

275 किलोग्राम वजनी लड़के को कई तरह की दिक्कतें हो रही थीं।

पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। 20 विशेषज्ञों ने जोखिमों का आकलन किया और परिवार से मशविरा कर सर्जरी का निर्णय लिया। सर्जरी के केवल तीन दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

अच्छी खबर | सरकार ने एमबीबीएस की 375, पीजी और डीएनबी की 103 सीटें बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया

दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार मेडिकल कॉलेजों में यूजी, पीजी और सुपर स्पेशियलिटी की सीटों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत एमबीबीएस यूजी में 375 सीटें बढ़ेंगी, वहीं पीजी और डीएनबी में 103 सीटों के साथ-साथ बीडीएस की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह का कहना है कि इसका मकसद सरकारी अस्पतालों में योग्य मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स की कमी को दूर करना है। इसके तहत नए चिकित्सा संस्थानों में सीटों का विस्तार, मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार और पोस्ट-ग्रेजुएट और एडवांस मेडिकल प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल और गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल से जुड़े निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 150-150 की सीटें प्रस्तावित की गई हैं। इससे 300 यूजी सीटें बढ़ जाएंगी। इस रोडमैप में दिल्ली के सरकारी मेडिकल संस्थानों में 103 और पीजी और डीएनबी सीटें जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

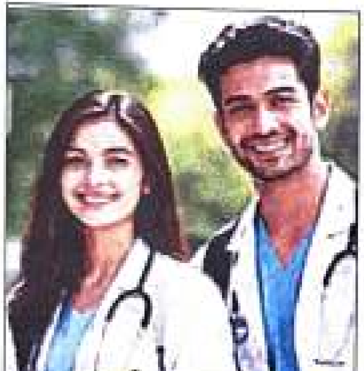

इन मेडिकल संस्थानों में बढ़ेंगी पीजी और डीएनबी सीटें

- बीएसए मेडिकल कॉलेज में 24 एमडी/एमएस सीटें
- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 35 एमडी/एमएस सीटें
- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डीएनबी की 18 सीटें
- दीप चंद बंधु अस्पताल,में डीएनबी की 8 सीटें
- जीटीबी में डीएनबी की 2 सीटें
- यूसीएमसी और जीटीबी अस्पताल में एमडी/एमएस की 4 सीटें
- गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में 2 डीएनबी सीटें
- संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में डीएनबी की 4 सीटें
- भगवान महावीर अस्पताल में डीएनबी की 2 और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एमडी की 4 सीटें

हालात अब भी पहले ही की तरह की थी। इस बैठक में व्यापारियों ने निर्देश दिए थे। खासकर जिला स्तर

इस वर्ष मच्छररोधी दवा के छिड़काव में 61% कमी, बढ़ सकते हैं डेंगू के मरीज

निहाल सिंह • जागरण

नई दिल्ली: राजधानी में एक ओर डेंगू के खतरनाक डेनवी-2 स्ट्रेन के मरीजों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, वहीं एमसीडी की सुस्ती से खतरे की घंटी बज गई है। मच्छररोधी दवा के छिड़काव और जांच की जिम्मेदारी एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन विभाग की सुस्ती से जांच और दवा का छिड़काव दोनों में कमी आई है। जानकारी के अनुसार, 2025 की तुलना में 2026 में विभाग की सक्रियता में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां 61 प्रतिशत कम घरों में दवा का छिड़काव हुआ, वहीं घरों में डीबीसी (डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स) द्वारा होने वाली जांच में 8.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे मच्छरों के पनपने का खतरा और बढ़ गया है।

जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी से आठ अगस्त 2026 तक निगम ने 2,75,767 घरों में मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव किया। वहीं, एक जनवरी से नौ अगस्त 2025 तक निगम ने 7,03,793 घरों में मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव किया था। यानी इस वर्ष करीब 4.28 लाख कम घरों में छिड़काव हुआ। यानी छिड़काव में 61 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह मच्छरों के

पिछले वर्ष से इस बार डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की तरफ से की जाने वाली जांच में आई 8.3 प्रतिशत की कमी

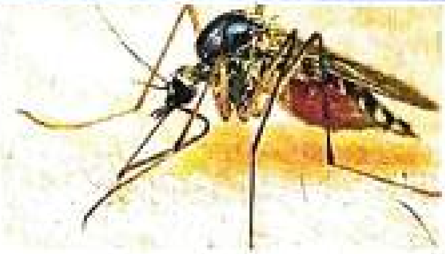

प्रजनन की जांच के लिए घरों में किए गए डोर-टू-डोर निरीक्षण भी कम हुए हैं। इस वर्ष अब तक 2,32,08,873 बार घरों व अन्य संपत्तियों का निरीक्षण किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2,53,19,526 थी। यानी इस वर्ष करीब 21.11 लाख कम निरीक्षण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 प्रतिशत कम हैं।

जांच कम होने से इस बार नोटिस भी जारी हुए कम: इस बार जांच कम होने का असर मच्छरों के लार्वा मिलने से संबंधित आंकड़ों पर भी साफ दिख रहा है। इस वर्ष अब तक की जांच में 82,870 घरों में मच्छरों का प्रजनन पाया गया, जबकि 2025 में यह संख्या 1,14,451 थी। यानी इस बार मच्छरों के लार्वा मिलने के आंकड़ों में 27 प्रतिशत की कमी पाई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर घरों में होने वाले निरीक्षण की संख्या कम न होती तो घरों में मच्छरों की उत्पत्ति की संख्या ज्यादा देखी जाती। इससे नोटिस भी कम जारी हुए। पिछले वर्ष 85,135 लोगों को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी संख्या घटकर 69,203 रह गई है। वहीं, मच्छरों की उत्पत्ति पाए जाने पर शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2025 में 16,384 अभियोजन शुरू किए गए थे, जबकि इस वर्ष अब तक सिर्फ 6,544 अभियोजन शुरू हुए हैं। यानी करीब 60 प्रतिशत की कमी आई है।

2,75,767 घरों में इस वर्ष अब तक मच्छररोधी दवाओं का किया गया है छिड़काव

7,03,793 घरों में 2025 में मच्छररोधी दवाओं का किया गया था छिड़काव

खबर विस्तार से पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

शिक्षा मंत्री ने कहा, परीक्षा व्यवस्था की कमियां दूर कर NTA दे रिपोर्ट

समीक्षा कर हर स्तर पर छोटी कमियों की पहचान करके, उसे दूर भी करें

पेपर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी दिए निर्देश, रिपोर्ट देनी होगी

■ NBT रिपोर्ट , नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि परीक्षा कराने की अपनी पूरी व्यवस्था की बारीकी से जांच करें। जहां भी कमी मिले, उसे दूर किया जाए और इसके लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी दें। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े पहले से तय नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। परीक्षा की तैयारी से लेकर उसके आयोजन तक किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर गोपनीय कामकाज और प्रश्नपत्र जैसी संवेदनशील चीजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

'गोपनीय कामकाज जैसे पेपर से जुड़ी सुरक्षा मजबूत करें'

जोशी ने कहा कि गोपनीय कामकाज के लिए अलग और सुरक्षित कमरे बनाने, इंटरनेट से पूरी तरह कटे कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करने और संवेदनशील जगहों पर मोबाइल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा कराने की व्यवस्था को तेजी से लागू करने को कहा गया है। इंटरनेट से कटे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को 'एयर-गैप्ड सिस्टम' कहा जाता है। ऐसे सिस्टम में सेंध लगाने या गोपनीय जानकारी चोरी होने का खतरा कम होता है। सरकार ने NTA में कर्मचारियों और अधिकारियों के स्तर पर भी बदलाव शुरू किए हैं।

IANS

शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी, NTA के डीजी अभिषेक सिंह मौजूद रहे।

री-टेस्ट के फैसले के बाद बुलाई मीटिंग

NTA ने नेट की 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की है लेकिन तीन विषयों के री-टेस्ट का फैसला लिया था। उसके अगले दिन सोमवार को शिक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

'पेपर में बेसिक भी गलत था'

3 विषयों के प्रश्नपत्र में गलतियों के बाद NTA ने एक कमिटी बनाई, जिसने प्रश्नपत्रों की जांच की। सोशियोलॉजी के पेपर में तो स्पेलिंग और व्याकरण की ऐसी गलतियां थीं, जो होनी ही नहीं चाहिए थीं। कुछ उम्मीदवार ने यह भी आरोप लगाया कि पेपर के कुछ हिस्से AI-जनरेटेड लग रहे थे। उम्मीदवारों ने बताया था कि Ritzer को Putzer, Parsons को Parsow, Ghurye को Ghunye और A R Desai को A K Desai लिखा गया था। इसलिए इन तीनों विषयों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है। NTA ने री-एग्जाम की डेट भी तय कर दी है। इंग्लिश का एग्जाम 9 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का एग्जाम 9 सितंबर को दोपहर 3 से 6 बजे तक होगा। सोशियोलॉजी का एग्जाम 10 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक होगा।

छात्रों के हितों के लिए सुधार जरूरी: उपराष्ट्रपति

■ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना और ईमानदार छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का मूल्यांकन केवल अंकों से नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता से होना चाहिए।

NTA की गलती की सजा छात्र क्यों भुगतें: राहुल

■ यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दोबारा कराए जाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि NTA की गलती की सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। राहुल ने सवाल उठाया कि NTA की नेतृत्व व्यवस्था की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है। वर्षों तैयारी करने वाले छात्रों को दोबारा फीस, यात्रा और परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल ने छात्रों की समस्याएं सुनने और लंबित मुद्दों का समाधान निकालने का आग्रह किया है।

NBT

आप पर असर

NTA ने परीक्षाओं के लिए नई टीम बनाई है। पेपर तय होने के बाद चार स्तरों पर जांच की व्यवस्था भी होगी। आशा है कि इससे गलतियां नहीं होंगी। यूजीसी नेट जून परीक्षा में इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के रीटेस्ट में एग्जाम सेंटर आवेदकों की प्राथमिकता के हिसाब से दिए जाएंगे। इससे उन्हें सहूलियत होगी क्योंकि सेंटर को लेकर भी आवेदकों के मन में चिंताएं हैं। परीक्षा के लिए अडिशनल फीस भी नहीं ली जाएगी, जो ली भी नहीं जानी चाहिए थी।

स्वतंत्रता दिवस से पहले छापेमारी

एयर इंडिया के 500 पायलटों का डोप टेस्ट

टाटा मेमोरियल तकनीकी साझेदार, मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल जुड़ेंगे

हर राज्य में कैंसर का सरकारी केंद्र 28 राज्यों में बनेगा हब-स्पोक नेटवर्क

हिमांशु अरविंद मिश्र

नई दिल्ली। कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े, इसके लिए देश के 28 राज्यों में सरकारी कैंसर उपचार का हब-स्पोक नेटवर्क विकसित करने की सिफारिश की गई है। संसदीय स्थायी समिति ने हर राज्य में एक सरकारी अस्पताल को मुख्य कैंसर केंद्र और उसके साथ एम्स, सरकारी मेडिकल कॉलेज व अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ने पर जोर दिया गया है।

समिति ने कैंसर की जांच, उपचार, प्रशिक्षण और मरीजों की देखभाल के मानकों को बेहतर बनाने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर को राष्ट्रीय तकनीकी साझेदार बनाने की सिफारिश की है। मरीज को बड़े कैंसर अस्पताल भेजने के बजाय पहले जिला स्तर पर जांच और विशेषज्ञ की ऑनलाइन सलाह मिलेगी।

मरीज को क्या फायदा?

■ शुरुआती जांच और कैंसर की पहचान स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। ■ जटिल मामलों को स्टेट कैंसर हब भेजा जा सकेगा। ■ मुंबई-दिल्ली जैसे बड़े शहरों की दौड़ कम होगी। ■ जिला अस्पतालों के डॉक्टरों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिलेगा। ■ पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और उपचार की गुणवत्ता में एकरूपता आएगी। ■ गंभीर मरीजों के लिए हब-स्पोक रेफरल व्यवस्था विकसित होगी। ■ कैसे काम करेगा हब-स्पोक मॉडल? ■ स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर या जटिल मामलों को स्पोक सेंटर के जरिए स्टेट कैंसर हब भेजा जाएगा।

650 करोड़ में मुख्य केंद्र, 400 करोड़ में इकाई

समिति के अनुसार, एक मॉडल कैंसर केंद्र तैयार करने में करीब 650 करोड़ रुपये और सालाना करीब 120 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। वहीं, इससे जुड़े जिला या मेडिकल कॉलेज स्तर के केंद्र के लिए करीब 400 करोड़ रुपये शुरुआती लागत और 40 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान है।

मेडिकल सीटें बढ़ाने से नहीं चलेगा काम

समिति ने कहा कि कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले विशेषज्ञों की उपलब्धता कम है। इसलिए केवल मेडिकल सीटें बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों और संबद्ध स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करनी होगी।

टीएमसी के लिए अकेले संभव नहीं

समिति का मानना है कि देशभर में इतने हब और स्पोक तैयार करना अकेले टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए पहले से मौजूद सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की क्षमता का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय कैंसर देखभाल नेटवर्क को मजबूत किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों की कमी सबसे बड़ी चुनौती

समिति ने ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट समेत प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को बड़ी चुनौती बताया है। केवल मेडिकल सीटें बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई गई है।

■ **क्या है हब-स्पोक व्यवस्था?**...इसमें एक बड़े सरकारी अस्पताल को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। उससे जुड़े मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सहयोगी केंद्र की तरह काम करेंगे। मुख्य केंद्र से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह, जांच की विशेषज्ञता, उपचार संबंधी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण छोटे केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।